



दैनिक

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित

# चम्बल सुखी

उत्कृष्ट एवं सफल प्रकाशन के 37 वर्ष

निष्पक्ष एवं निर्भीक विचारों का प्रवक्ता



आज का

तापमान

अधिकतम

35 डिग्री

न्यूनतम

19 डिग्री

## संक्षिप्त समाचार

### मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली एवं धुलंडी की शुभकामनाएं

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली एवं धुलंडी (13 व 14 मार्च) के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि होली का यह त्यौहार जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिचायक हैं। रंगों और खुशियों से लबरेज यह पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सद्भाव को बढ़ाने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे आपसी प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता के साथ रंगों के इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें।

### पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी, राजदूत को एंटी देने से अमेरिका का इनकार, एयरपोर्ट से ही लौटाया

इस्लामाबाद, एजेंसी। अमेरिका में पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी भरी घटना घटी है। यहां शीर्ष पाकिस्तानी राजनयिक को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया और विवादास्पद वीजा संदर्भों के कारण निर्वासित कर दिया गया। यह जानकारी पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को दी। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत के वागम कश्चित तौर पर एक निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने पर अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने विवादास्पद वीजा संदर्भों के लिए वागम को तत्काल निर्वासित कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह कदम किन विशिष्ट चिंताओं के कारण उठाया।

### बिहार में पिता ने 4 बच्चों को दूध में डूबा जहर, 3 की तड़प-तड़प कर मौत

आरा, एजेंसी। बिहार के आरा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने चार बच्चों को जहर देकर मारने के बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस हृदयविदारक घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि पिता और एक अन्य बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना आरा जिले में मंगलवार रात को घटी। मृतक बच्चों की पहचान और उम्र अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस के अनुसार, अरविंद कुमार नामक व्यक्ति ने अपने बच्चों को दूध में जहर मिलाकर पिता दिया, और फिर स्वयं भी जहर का सेवन कर लिया।

## मोहन सरकार का 4.21 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट

### कोई नया टैक्स नहीं, गरीबों को कई सौगातें और उद्योगों को 30000 करोड़ का इंसेंटिव

भोपाल, ब्यूरो। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार की ओर से आज बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की। उन्होंने कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दू जहां अंधेरा है... जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2025-26 का बजट जोरी बेस्ट बेस्ट प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश है।



### कोई नया टैक्स नहीं

सरकार की ओर से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। टैक्स की सभी प्रक्रिया को पहले जैसा ही रखा गया है। 2025-26 के बजट में प्रदेशवासियों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है।

### तीन लाख से अधिक को रोजगार का दावा

2025-26 का वर्ष सरकार उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाएगी। प्रदेश में 14 हजार 500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इन उद्योगों के जरिए तीन लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की, जिससे उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए

प्रोत्साहन नीतियों के तहत इंसेंटिव दिए जाने का भी एलान किया गया है। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार की ओर से पांच साल में उद्योगों को करीब 30 हजार करोड़ का इंसेंटिव दिया जाना प्रस्तावित है, जबकि इस साल इंसेंटिव के लिए तीन हजार 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल से 551 करोड़ अधिक है।

### गरीबों को योजनाओं का पैकेज देगी सरकार

बजट में मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा की गई। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को एक-दो योजनाओं की जगह, उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।

### किसानों के क्या खास?

बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम किसान कल्याण योजना के लिए पांच हजार 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

### उज्जैन सिंहस्थ के लिए क्या मिला?

2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर सरकार की ओर से बजट में दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे सिंहस्थ को लेकर रहे रही तैयारियों में और तेजी आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के कई काम लगातार हो रहे हैं, 2028 तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। बजट में लगातार इसके प्रावधान किए जा रहे हैं, इस बजट में 2000 करोड़ दिए जा रहे हैं।

### प्रदेश की रफतार बढ़ाने का लक्ष्य

सड़कों और पुलों के निर्माण एवं संभारण के लिए वर्ष 2025-26 में 16 हजार 436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से 34 प्रतिशत अधिक है। बजट में नई योजना का एलान किया गया है, क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना बनाई है। इस योजना के लिए 100 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में बताया गया कि अगले पांच सालों में एक लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पांच सालों में 500 रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस साल 3500 किलोमीटर नवीन सड़कें और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है।

### नगरीय विकास के लिए दो हजार करोड़

नगरीय विकास के लिए 18 हजार 715 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह पिछले यानी 2024-25 के बजट से करीब दो हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इससे प्रदेश में स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कार्य किए जाएंगे।

### जीरो बेस्ट बजटिंग प्रक्रिया अपनाई

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट की शुरुआत में कहा कि इस बार का बजट जीरो बेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि, सही योजना में, सही आकार और सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। आगामी वर्षों में बजट को और अधिक सार्थक, संतुलित व सरल बनाने के प्रयास

### पाकिस्तान ने कहा-सभी विद्रोही ढेर, कुछ बंधकों की भी मौत:

### बलूच लड़ाकों का दावा: 60 और पाकिस्तानी सैनिक मारे, आंकड़ा 100 से ज्यादा

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बुधवार देर 9:30 बजे दावा किया कि ट्रेन हाईजैक गतिरोध खत्म हो गया। सुरक्षाबलों ने सभी 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में कुछ बंधक भी मारे गए हैं। उधर, बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने कहा कि उसने आज 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, इससे पहले मंगलवार को 40 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की थी। अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। बीएलए का दावा है कि अब भी 150 बंधक उसकी कैद में हैं। अगर अगले 20 घंटे में पाकिस्तान सरकार ने बलूच कैदियों को रिहा नहीं किया तो इन सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा। ट्रेन हाईजैक पर पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे सैनिकों ने कई विद्रोहियों को नरक भेज दिया है।



### पाकिस्तानी सेना बोली- विद्रोही बम लगी जैकेट पहने

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स और सेना के जवान बलूच लड़ाकों को घेरे हुए हैं। विद्रोही विस्फोटक से लदे आत्मघाती जैकेट पहने हुए हैं, इससे बाकी बंधकों को रिहा कराने में मुश्किल हो रही है। वे इन्हें विद्रोहियों को नरक भेज दिया है।

### होली से पहले मुख्यमंत्री योगी ने 1.86 करोड़ परिवारों को दिया तोहफा

लखनऊ, एजेंसी। होली के ठीक पहले बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलिंडर रिफिल के लिए 1,890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। इस योजना का शुभारंभ लखनऊ के लोकभवन सभागार में सीएम योगी ने किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जहां गैस कनेक्शन के लिए घूस देना पड़ता था, अब यह सुविधा देश में 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही होली और दीपावली पर गैस सिलिंडर भी मुफ्त दिया जा रहा है। इस बार होली और रमजान एक साथ हैं, तो सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। उज्वला योजना को 2016 में शुरू किया गया था, जिसके तहत देश भर में 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिले। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ लोग



योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 के चुनाव में हमने वादा किया था कि 2022 में सरकार बनने पर होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा। उस समय से हर साल यह योजना चल रही है ताकि लोग पर्व और त्यौहार अच्छे से मना सकें। इस बार होली और रमजान दोनों साथ हैं, इसलिए सभी को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले एक गैस कनेक्शन के लिए 25-

30 हजार रुपए की घूस देनी पड़ती थी और त्यौहारों पर सिलिंडर भी नहीं मिल पाते थे। यह योजना गरीब माताओं को धुंध से बचाने के लिए शुरू की गई है और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। यूपी में 80 हजार राशन डीलर 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्डधारकों के जरिए 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। 2017 में ई-पाश मशीनों के जरिए राशन वितरण में पारदर्शिता लाई गई, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगी। कोविड काल में जब लोग परेशान थे, तब से लगातार पांच साल हो गए, हर महीने देश में 80 करोड़ लोगों और यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और बेटियों के कल्याण के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 22 लाख बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रति बेटी 25 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है, जबकि 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई है।

### निकाय चुनाव में शानदार जीत के लिए जनता-जनार्दन का आभार : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 नगर निगमों में विजय हासिल की है। वहीं, मानेसर से निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. इंद्रजीत यादव ने जीत का परचम लहराया है। चुनाव में कांग्रेस को एक भी मेयर पद नहीं मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस जीत के लिए मैं प्रदेश की जनता-जनार्दन का आभार जताता हूँ। ये जीत जनता की जीत है और ये पीएम मोदी जी की

गारंटी और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। हरियाणा में टिप्पल इंजन सरकार बनाने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने फरीदाबाद की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा, फरीदाबाद के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है और देश भर में ऐसी बड़ी जीत कभी नहीं हुई है। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस

### अपार आईडी न बनाने वाले मद्रसों को चेतावनी, समय से काम पूरा न होने पर रद्द हो सकती है मान्यता

बाराबंकी, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 38 मद्रसों पर मान्यता खत्म होने की तलवार लटकती है। इन मद्रसों की तरफ से 'अपार' आईडी न बनाने में लापरवाही की गई है। यह आईडी मद्रसों के लिए अनिवार्य की गई है। विभाग की ओर से इनको मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बालेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अपार आईडी बनाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। रमजान में कुछ मद्रसे बंद होते हैं। इस कारण यहां पर 'अपार' आईडी बनाने की प्रक्रिया कुछ धीमी है। उनको कई बार मौखिक रूप से चेतावनी दी गई। लापरवाही बरतने वाले 38 मद्रसों को कड़ी चेतावनी दी गई है। समय पर कार्य पूरा न होने पर नोटिस दी गई है। अगर तय समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ, तो मान्यता रद्द भी की जा सकती है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने कहा कि चेतावनी के बाद मद्रसा प्रबंधकों की ओर से काम में तेजी लाई गई है। ज्ञात हो कि एक राउंड इंटर तक के सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं। जिले में जनवरी से ही 'अपार' आईडी बनाने का काम चल रहा है। एक माह पहले ही समीक्षा होने के बाद निजी व सरकारी स्कूलों को चेतावनी दी गई तो काम कुछ तेज हुआ, लेकिन मद्रसों ने कोई तेजी नहीं दिखाई। इस वजह से वहां पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी गई है।

### राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश को बताया भंगेड़ी, बोलीं: भांग पीकर विधानसभा आते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं

पटना, एजेंसी। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच टकराव देखने को मिला। इसके बाद सदन से बाहर निकली राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश भंगेड़ी हैं। वह भांग पीकर विधानसभा आते हैं। वह महिलाओं को अपमानित करते हैं। राबड़ी देवी ने पहले हुए कार्यों को नहीं देखा है क्या? पहले बाजार, हाट नहीं था, तो व्यापार कैसे होता था? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दो बार सदन में हमें अपमानित कर चुके हैं।

मेरा नहीं, पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले काम नहीं होता था, फाइल देखिए कि क्या-क्या काम हुआ था। बिहार की जनता नहीं जानती है क्या? हम लोगों ने महिलाओं, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों, सभी के लिए काम किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार 2005 के पहले नहीं थे? पत्रकारों से भी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पहले हुए कार्यों को नहीं देखा है क्या? पहले बाजार, हाट नहीं था, तो व्यापार कैसे होता था? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दो बार सदन में हमें अपमानित कर चुके हैं।

### उत्तर प्रदेश के संभल में होली को लेकर मस्जिदों को तिरपालों से ढकने का काम शुरू

संभल, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के संभल में होली को लेकर सड़क किनारे स्थित मस्जिदों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से उन्हें तिरपालों से ढकने की कवायद शुरू कर दी गई है। एएसपी श्रीशचंद्र ने बताया कि सभी पक्षों की सहमति के बाद होली के मार्ग पर पड़ने वाले सभी मस्जिदों को ढका जा रहा है। पूर्व की भांति यह व्यवस्था हो रही है। जुलूस के रास्ते में 10 धार्मिक स्थान पड़ते हैं, जिन्हें ढका जा रहा है। दोनों पक्षों के लोगों से इसको लेकर



बातचीत की गई है। दोनों ही पक्षों ने इस फैसले पर सहमति जताई है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने त्योंहों से पहले सुरक्षा-व्यवस्था के बारे में

जानकारी देते हुए कहा था कि शांति समिति की बैठकें की गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक सेंक्टर मस्जिदों को अपने क्षेत्र में भ्रमण करने को कहा गया है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी हो रही है। पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में हुए प्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। गृह मंत्रालय ने जारी किए गए एक आदेश में कहा कि

### जम्मू कश्मीर: देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहन होगा गृह मंत्रालय ने JKIM पर पांच साल के लिए लगाया प्रतिबंध

जम्मू, एजेंसी। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन को एक अवैध संघ घोषित कर दिया है और अगले पांच वर्षों तक उसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यह संगठन अवैध गतिविधियों में संलग्न है, जो देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। गृह मंत्रालय ने जारी किए गए एक आदेश में कहा कि



जेकेआईएम देश के खिलाफ कार्य कर रहा है और इसके कार्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है। इसके तहत संगठन की सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है और इसके सदस्य या सहयोगी किसी भी

प्रकार की सक्रियता में लिप्त जाएं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को संगठन के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय के इस निर्णय को देशभर में सुरक्षा मामलों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को रक्षा के लिए आवश्यक कदम है।



# सुकन्या समृद्धि योजना कन्या अभिभावकों के लिए वरदान

## कलेक्टर ने की योजनान्तर्गत खाते खुलवाने की अपील

श्यापुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जनहितकारी सुकन्या समृद्धि खाता योजना में सभी आम जनमानस, प्रयुद्ध नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों, बेटीयों के अभिभावकों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सहित अधिकारियों से सहभागिता एवं सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि, बेटी है जहां खुशियां हैं वहां, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कन्या अभिभावकों के लिए यह योजना वरदान है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने इस



योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां हैं तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा

सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये से शुरू किया जा सकता है। बच्चों की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्धि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इस पर 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि प्रदान की जाती है, यदि कोई व्यक्ति मात्र एक हजार रुपये मासिक जमा करता है तो 15 साल में 1 लाख 80 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी, जिस पर 21 वर्ष के उमरात परिपक्वता के समय 5 लाख 64 हजार 613 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार इस महत्वाकांक्षी योजना से आवक में छूट का लाभ भी मिलता है और देश के किसी भी

हिस्से में स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्लफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते में न्यूनतम 250 रुपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। कलेक्टर ने कहा है कि, अधिक जानकारी के लिए श्यापुर के डाक घर के कार्यालय पर्यवेक्षक, निरीक्षक डाक घर श्यापुर एवं विकास अधिकारी पोस्ट मास्टर श्यापुर तथा जिले के डाकघर के पोस्ट मास्टर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने सभी से इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग एवं सहभागिता करने की अपील की है जिससे हर बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर हो सके।

## चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के सुझाव लिये जायेगे

### आयोग ने राजनीतिक दलों से अनिराकृत मुद्दों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक मांगे सुझाव

श्यापुर ब्यूरो। भारत निर्वाचन आयोग ने कानून ढांचे के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से ईआरओ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर अनिराकृत प्रकरणों की 30 अप्रैल, 2025 तक जानकारी मांगी है। आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को विकसित रूप से पत्र भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साप्ताहिक भारत निर्वाचन आयोग एक सम्मेलन किया गया था। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने और प्राप्त सुझावों पर

नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह भी किया है। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 28 हितधारक हैं, जिसमें राजनीतिक दल एक प्रमुख हितधारक है। जिन्हें संविधान और विवेक ढांचे के तहत चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े सभी पहलुओं में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को जारी किए गए पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, मैनूअल और हैडबुक (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

## चना, सरसों फसल के पंजीयन अब 17 मार्च तक

श्यापुर ब्यूरो। जिले में समर्थन मूल्य पर चना, सरसों फसल विक्रय करने हेतु विपणन वर्ष 2025-26 में ई-उपार्जन पोर्टल पर चना, सरसों फसल के पंजीयन 33 केन्द्रों पर अब 17 मार्च 2025 तक किये जा सकते हैं। उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया ने बताया कि चना, सरसों फसल के विक्रय के लिए आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित आवदा, विपणन सेवा सहकारी संस्था मरहाल, वृहत्कार सहकारी संस्था मरहाल बड़ोदा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बोरदादेव, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नयागांव तेहखण्ड, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित राडेय, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित तुलुड, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित फिलोजपुरा, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित तलावडु, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जलालपुरा, सेवा सहकारी संस्था कानपुर, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ओझपुरा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित रघुनाथपुर, विपणन सहकारी संस्था वीरपुर, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित विजयपुर, विपणन सहकारी समिति विजयपुर, सेवा सहकारी समिति सहस्रम, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित श्योपुर, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जलालपुरा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नागदा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सोईनाल, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नागरावडा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित आसीदा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बीजपुर, सेवा सहकारी संस्था कन्यापुरा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गोहेड, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित दातरद, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित मानपुर, सेवा सहकारी संस्था सोडवा, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जावदेकर, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित तलावदा, सेवा सहकारी संस्था युगनोवादा, वृहत्कार सहकारी संस्था मर्यादित पाण्डेला पर पंजीयन कराये जा सकते हैं। इसके अलावा एम.पी.किसान ऐप तथा सशुल्क में एम.पी. ऑनलाइन क्रियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर क्रियोस्क, लोकसेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सारबर् कैफे पर भी फसल पंजीयन कराया जा सकता है।

# मार्च तक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूर्ण करें, फार्मर रजिस्ट्री में गति बढ़ायें-डीएम

## धारा 248 और 250 अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश, कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों को बैठक आयोजित

श्यापुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी अविवादित नामांतरण के प्रकरण समय सीमा में निराकृत करें। नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों में बैठकर राजस्व मामलों की सुनवाई करें तथा प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में गति बढ़ाने तथा मार्च तक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिये। अभी तक जिले में 56.64 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि जमीनों में अतिक्रमण के मामलों में संबंधितों पर धारा 248 एवं 250 अंतर्गत कार्यवाही की जाये। वे आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने अविवादित नामांतरण की राजस्व न्यायालयों वार समीक्षा करते हुए



कहा कि 13 न्यायालयों में से रघुनाथपुर, प्रेमसर, वीरपुर, मानपुर का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है। सबसे कम प्रतिशत 78.79 प्रतिशत तहसीलदार कराहल की है। इसी प्रकार अविवादित बंटवारे में नायब तहसीलदार पहला, गोरस एवं तहसीलदार वीरपुर की प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है, गसवानी का प्रतिशत 57.89 है। सीमांकन के प्रकरणों में तहसील वीरपुर सहित नायब तहसीलदार वृत्त अगरा, पहला, गोरस, मानपुर, रघुनाथपुर का निराकरण शत प्रतिशत है। सीमांकन के कुल 36 प्रकरण लंबित है।

सभी तहसीलों में 39 लाख 65 हजार 775 रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि अपने अपने क्षेत्र में तलघरो के निर्माण पर निगरानी रखें तथा तलघरो का निर्माण पर्वस अनुमतियों के साथ किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए 100-100 हेक्टरभूमि के चक को चिह्नित करने की कार्यवाही करें। इसी के साथ उन्होंने एसडीएम विजयपुर को नगरीय क्षेत्र में साफ-सफाई अभियान चलावने के निर्देश भी दिये। बैठक में एसडीएम श्यापुर श्री मनोज गडवाल, कराहल श्री वीरस श्रवास्वत, विजयपुर श्री अभिषेक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। बताया गया कि प्रेमसर वृत्त में 5 लाख से अधिक एवं गोरस में साढ़े पांच लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई है। इस माह 11 मार्च तक

## समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन 31 मार्च तक, 2600 रुपये प्रति किंटल पर होगी खरीदी

श्यापुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन का कार्य जारी है, जिले में 33 पंजीयन केन्द्र बनाये गये हैं। जिन पर किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा रहा है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। शासन द्वारा 2600 रुपये प्रति किंटल की दर से गेहूँ की खरीदी की जायेगी, इसके अंतर्गत 2425 रुपये प्रति किंटल की दर निर्धारित की गई है, जबकि 175 रुपये प्रति किंटल के मान से राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनास दिया जायेगा। इस प्रकार एक किंटल के विक्रय पर किसानों को 2600 रुपये प्राप्त होंगे। फूड ऑफिसर श्री सुनील शर्मा ने बताया कि पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था श्यापुर जिले की 33 सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर की गई है, इसके साथ ही एम.पी. किसान एप के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन किया जा सकता है। किसान स्वयं के मोबाइल से एम.पी. किसान एप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा एम.पी. ऑनलाइन क्रियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर क्रियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से भी किसान पंजीयन करा सकते हैं।

## 13 मार्च को 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी आयोजित, परीक्षा में सभी छात्रों को परीक्षा केन्द्र पर प्राप्त: 08 बजे तक पहुँचना अनिवार्य होगा

### प्रातः 08.30 के बाद नहीं दिया जायेगा प्रवेश, परीक्षा केन्द्र पर अनुचित सामग्री, मोबाइल, घडियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहेंगे पूर्णतः प्रतिबन्धित

भिण्ड ब्यूरो। माध्यमिक शिक्षा विभाग मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा दिनांक 13 मार्च 2025 को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में सभी छात्रों को परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 08 बजे तक पहुँचना अनिवार्य होगा। प्रातः 08.30 के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सभी पालक अपने बच्चों को निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री नहीं ले जायें, मोबाइल, घडियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

## गृह निर्माण सहायक संस्था के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

श्यापुर ब्यूरो। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा संसद रविदास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित श्यापुर के संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु उप अवेक्षक श्री यशपाल सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उक्त संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 मार्च को महिला पदों के विनिश्चय हेतु संचालक मंडल की बैठक के लिए सूचना जारी की जायेगी तथा 20 मार्च को बैठक आयोजित की जायेगी। आम सभा की सूचना एवं निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने की तिथि 21 मार्च रहेगी। नामांकन पर प्रस्तुत किये जाने की तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जाँच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन 29 मार्च को होगा। नाम वापसी एवं निर्वाचन लक्ष्य वाले अंतिम उम्मीदवारों की सूची तथा चुनाव चिह्न का आवंटन 30 मार्च को किया जायेगा। 4 अप्रैल को विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना संपन्न कराई जायेगी। रिक्त स्थानों एवं वृत्तिक संचालकों के सहस्रजन की तिथि 5 अप्रैल रहेगी। रिक्त स्थानों के नामांकन की तिथि 7 अप्रैल एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु 8 अप्रैल को सूचना जारी की जायेगी। इसके उपरान्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन 11 अप्रैल को होगा।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन



श्यापुर ब्यूरो। प्रधानमंत्री कलेज ऑफ़ एक्सलेंस शसकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्यापुर में महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री मनोज सराफ एवं प्राचार्य डॉ एसडी राठौर की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सराफ ने कहा कि वर्तमान समय में एआई की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है, इस नवीन तकनीकी के माध्यम से कार्यों में आसानी हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.एस.डी.राठौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि आज का युग एआई, मशीन लर्निंग एवं एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी का युग है। जिसके द्वारा किसी भी समस्या को पल भर में हल किया जा सकता है। वका के रूप में उपस्थित आईआईटी इंडिया के प्राचार्य प्रभारी डॉ.लक्ष्मीकांत राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.विपिन विहारी शर्मा, डॉ.सुभाष चंद्र, डॉ.ओ.पी.शर्मा, डॉ.रमेश भारद्वाज, प्रो.अरविंद दोहरे, डॉ.संगीता शाक्य, डॉ.उर्मिला बाथम, डॉ.करण सिंह सैनी, डॉ.दीपक कुमार शर्मा, प्रो.कमलेश निगम एवं प्रो.विकास जाट, डॉ सीमा चौकसे सहित एक सैकड़ छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

## महिला सशक्तिकरण अभियान अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

भिण्ड ब्यूरो। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा माननीय श्री उमेश उपाखंड, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण अभियान (08.मार्च से 12 मार्च 2025) अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के संबंध में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित श्री हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश भिण्ड ने उपस्थित जनों को महिलाओं के अधिकारों एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, एफिस्ट अटैक पीडिंटों के लिए विधिक सेवा योजना, 2016 के अलावा में एवं साइबर अपराधों आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर रहे ही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर, न्यायसौचित्य तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, इसके साथ ही समाज

## स्वी उपार्जन वर्ष 2025-26 में गेहूँ उपार्जन हेतु किया जा रहा है पंजीयन, गेहूँ उपार्जन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च

### जिले में कुल 38 संस्थाओं पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा है उपलब्ध किसान ऐप से मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है पंजीयन

भिण्ड ब्यूरो। जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने जिले के समस्त किसान बंधुओं को सूचित कर कहा है कि वर्तमान में स्वी उपार्जन वर्ष 2025-26 में गेहूँ उपार्जन हेतु पंजीयन किया जा रहा है, इस हेतु जिले के सभी विकासखण्ड में कुल 38 संस्थाओं पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है साथ ही जिले में 158 एमपी ऑनलाइनएक्सपीएससी केन्द्रों पर भी 50% रुपये पंजीयन के मान से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है साथ ही किसान ऐप से

मोबाइल के माध्यम से भी पंजीयन किया जा सकता है, इसका लाभ उठाते हुये तेजी से अपना पंजीयन करायें, पंजीयन हेतु खसरा खतीनी, आधार कार्ड, सप्पा आईडी, बैंक पासबुक और ऐसा मोबाइल नंबर जोकि आधार और बैंक खाते में जुड़ हो को लेकर ही केन्द्र पर जायें। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। साथ ही किसानों से अनुरोध है कि आगामी साप्ताह से गेहूँ की खरीदी चालू हो जायेगी। पंजीयन किसान अपने गेहूँ को खरना लाकर

## जिले की समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) संस्थाओं पर स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन

### नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ थीम पर लगाए गए शिविर



भिण्ड ब्यूरो। म.प्र. शासन आयुष विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) संस्थाओं पर प्रतिमाह विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला आयुष अधिकारी डॉ. नीलम कुशवाहा के नेतृत्व में आज जिले की समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) संस्थाओं पर नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ थीम पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। म.प्र. शासन आयुष विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर लाने तथा नवजात एवं शिशुओं के बेहतर विकास, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा बार-बार होने वाली व्यक्तियों जैसे न्यूमोनिया, कोणुषण आदि को दूर करने में आयुष चिकित्सा के योगदान को बढ़ाने हेतु इन शिविरों का आयोजन किया गया। डॉ. नीलम कुशवाहा के अनुसार प्रायः ग्रामीण

प्रदाय की गई। उक्त अवसर पर उपस्थित श्री सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला भिण्ड उपस्थितजनों को बताया गया कि महिलाएं तथा बच्चों नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/घर के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में श्री हनुमंत बौहरे, श्री अमित थापक, एलएचडीसी अधिवक्तागण एवं वन स्टॉप सेंटर का स्टॉफ, श्री मंजर करना, ट्रेनिंग, फिसिंग आदि के बारे में भी सरलतम भाषा में जानकारी



आयुष चिकित्सा को युवाओं और बुजुर्गों तक ही सीमित रखते हैं जबकि यह नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य की भी बहुत कारगर है। हमारी संस्थाओं पर सामुदायिक आयुष चिकित्साधिकारी इसमें महती भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में जिले में 21 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) संस्थाएं संचालित हैं।

## दिनांक 14 मार्च होली को 04 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा, मदिरा की बिक्री पूर्णतः बन्द रहेगी - कलेक्टर

भिण्ड ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 'होली' (जिस दिन रंग खेला जाये) अर्थात् दिनांक 14 मार्च 2025 को सांय 04:00 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं एफ.एल.-3 होटलबार, एफ.एल.-9, 9श्कर, सी.एस.-1 (बी), डी. 1. बी. 3 इकाईयों तथा देशी मदिरा स्टोर्स मद्यभागडगारों को उक्त अवधि में पूर्णतः बंद रखा जाना तथा मादक की बिक्री निषिद्ध रखी जाने आदेश दिया है।

## भारत निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से करेगा बातचीत, आयोग ने राष्ट्रीय और प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दलों से अनिराकृत मुद्दों के लिए, 30 अप्रैल 2025 तक मांगे सुझाव

### भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित तौर पर बातचीत करने, ऐसी

बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर हल करने के निर्देश दिये थे। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह भी किया है। राजनीतिक दलों से ईआरओ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर अनिराकृत मुद्दों के लिए 30 अप्रैल, 2025 तक सुझाव भी मांगा है। आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साप्ताह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित तौर पर बातचीत करने, ऐसी



## गर्भावस्था व प्रसव उपरांत बीमारियों की रोकथाम के लिये किए जायेंगे विशेष प्रयास कलेक्टर ने ब्रिटानिया फाउण्डेशन के पदाधिकारियों से की चर्चा

ज्वालियर। मातृ मृत्यु (आईएमएआर) एवं गर्भावस्था व प्रसव उपरांत बीमारियों को कम करने के लिये जिले में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गर्भवती माताओं में अधिकांश एनीमिया की शिकायत मिलती है, इसको घरेलू और सामुदायिक स्तर पर लोहे की कड़ाई का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। ब्रिटानिया फाउण्डेशन ने इस दिशा में सकारात्मक कार्य करने हेतु कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान से बुधवार को उनके कार्यालय में मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की। ब्रिटानिया फाउण्डेशन की वैंगलर से पधारी सीएसआर प्रमुख सुश्री प्रियंका सिंह एवं जिला समन्वयक श्री जितेंद्र पाटीदार से कलेक्टर ने जिले में इस दिशा में विशेष कार्य करने के संबंध में चर्चा की। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव एवं डीपीएम श्री विजय भागवत भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने ब्रिटानिया फाउण्डेशन के पदाधिकारियों से जिले में गर्भवती



एवं बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिये किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। हर माह में दो बार आयोजित होने वाले हार्डिस्क प्रोग्रामों की वृत्तीय केंद्रों अंतर्गत इस माह भी 25 मार्च को ब्रिटानिया फाउण्डेशन द्वारा जिले की विभिन्न संस्थाओं पर एनीमिक एवं गंभीर एनीमिक गर्भवतीओं को प्राथमिकता पर लोहे की कड़ाई का प्रदर्शन करने की सहमति दी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में फूड बैंक वितरण के संबंध में भी फाउण्डेशन द्वारा अपनी सहमति

## बाल विवाह एवं सुरक्षित स्पर्श व असुरक्षित स्पर्श विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

ज्वालियर। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से बाल विवाह, सुरक्षित स्पर्श व असुरक्षित स्पर्श एवं पर्यावरण विषय पर शासकीय पदा राजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कम्प्यू में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 90 छात्राओं में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था के अध्यक्ष उमेश वशिष्ठ, महिला एवं बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी ज्योति गर्ग, सपोर्टर्स अरविंद कुशवाह उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अध्यक्ष उमेश वशिष्ठ द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में सभी को जानकारी दी व संस्था द्वारा किये



जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। इसके उपरांत महिला एवं बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी ज्योति गर्ग द्वारा सुरक्षित स्पर्श व सुरक्षित स्पर्श के संबंध में विस्तार से जानकारी दी व बताया कि बच्चों को किसी प्रकार से छूने की जरूरत नहीं है यदि कोई उन्हें परेशान करता है या छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना अपने टीचर, परिवार को सदस्यों या दोस्तों को दे साथ ही

प्रदान की गई है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फाउण्डेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग करें। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से भी समन्वय स्थापित कर कार्यों को और बेहतर ढंग से कराया जाए। फाउण्डेशन एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो जा रही कारवाइ की प्रतिमाह रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को प्रेषित करें। साथ ही हिताधिकारियों का स्वास्थ्य संबंधी फोलोअप भी नियमित किया जाए।

## पर्यावरण संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



ज्वालियर। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था द्वारा अभ्युदय ट्रस्ट नई दिल्ली सहयोग से पर्यावरण संरक्षण विषय पर शासकीय पदा राजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कम्प्यू में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 90 छात्राओं में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था के अध्यक्ष उमेश वशिष्ठ, महिला एवं बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी ज्योति गर्ग, सपोर्टर्स अरविंद कुशवाह उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अध्यक्ष उमेश वशिष्ठ द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में सभी को जानकारी दी व बताया कि पर्यावरण संरक्षण

का अर्थ है हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को हानि से बचना, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, वनस्पति और जीव-जंतु। इसका लक्ष्य है, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, और एक स्वस्थ और स्थायी भविष्य बनाना। उन्होंने बताया कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। इसके उपरांत विद्यालय में पोषारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार शर्मा, माध्यमिक शिक्षक राकेश दुबे, उमाशंकर शर्मा, शैलजा गुप्ता, कसान सिंह सिसोदिया उपस्थित थे।

## कम सम्पत्तिकर वसूली पर 1 एपीटीओ एवं 30 से अधिक करसंग्रहकों को नोटिस जारी करने के निर्देश निगमायुक्त ने की सम्पत्तिकर वसूली की समीक्षा, लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिए निर्देश

ज्वालियर। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने बुधवार को सम्पत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी एवं पिछले वर्ष से कम वसूली व वर्तमान में लक्ष्य की 30 प्रतिशत या उससे कम वसूली करने वाले 30 से अधिक कर संग्रहकों की वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित सम्पत्तिकर वसूली समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त श्री अर्जुन दुबे, उपायुक्त श्री एपीएस भदौरिया, श्री रजनीश गुप्ता एवं श्री मुकेश बंसल सहित सभी सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी एवं कर संग्रहक मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने अभी तक हुई वसूली की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी वसूली प्रभारियों को निर्देशित किया कि हर हाल में 110 करोड़ रुपये की सम्पत्तिकर की वसूली होनी चाहिए, इसके लिए सभी बड़े बकायदारों से वसूली के लिए प्रभावकी कारवाइ करें। कारवाइ में सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी के साथ संबंधित उपायुक्त भी मौजूद रहें। सम्पत्तिकर वसूली में किसी भी



प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए प्रत्येक कर संग्रहक अपने क्षेत्र के बड़े बकायदार के यहां प्रतिदिन तालाबंदी करें तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कारवाइ करें। कर संग्रहक आगामी समीक्षा बैठक में यह बताएं कि उनके क्षेत्र से वह कितनी वसूली करेंगे। समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय 9 व 10 के सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी एवं पिछले वर्ष से कम वसूली व वर्तमान में लक्ष्य की 30 प्रतिशत या उससे कम वसूली करने वाले 30 से अधिक कर संग्रहकों की वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी करने के

निर्देश दिए। निगमायुक्त ने कहा कि कम वसूली एवं लापरवाही करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नामांकन प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया सरल व सुलभ बनाए इसके साथ ही पेंमेंट जमा करने के लिए भी नगरिकों को वक्तु आर कोड के माध्यम से पेंमेंट जमा करने की सुविधा प्रदान करें। इसके साथ ही अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों व कर संग्रहकों को दिए।

## विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा यह बजट - मंत्री श्री सिलावट बजट में जल संसाधन विभाग के लिए 9196 करोड़ रुपये का प्रावधान

ज्वालियर। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं ज्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन ड्यूप्लेमेंट तैयार किया है। वित्त एवं उद्यम मुखांश मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि यह प्रस्ताव का विषय है कि वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में इस बजट में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान 7248 करोड़ 17 लाख 3 हजार रुपये था, जिसे इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 9196

करोड़ 21 लाख 58 हजार रुपये किया गया है। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध तथा संरक्षण कार्य के लिए रुपये 3930 करोड़ को कार्यालयिक स्थापना के लिए रुपये 11225 करोड़, नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए रुपये 1061 करोड़, केन-बेनाल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए रुपये 700 करोड़, लघु एवं लघुमत्त सिंचाई योजनाएँ के लिए रुपये 501 करोड़, कान्हा डायवर्सन क्लोज ड्रफ्ट परियोजना के लिए रुपये 300 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए रुपये 200 करोड़, बांध तथा नहरों के लिए रुपये 193 करोड़, नहरों तथा तालाब के लिए रुपये 162 करोड़, अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए रुपये 140 करोड़, सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्संस्थापना के लिए रुपये 128 करोड़, चैतनीखड़ा मध्यम परियोजना के लिए रुपये 90

करोड़, टेम मध्यम परियोजना के लिए रुपये 75 करोड़, निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था के लिए रुपये 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दायव्युक्त पद्धतियों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर -मिले जल हमारा तुम्हारा- के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र

में पेंतेहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदानीरा स्वरूप प्राप्त होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में रुपये 24 हजार 293 करोड़ की अनुमानित लागत की केन-बेनाल लिंक परियोजना एवं रुपये 35 हजार करोड़ की अनुमानित लागत की पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। तानी नदी पर तानी बैरिन मेगा रिचार्ज योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार से सहमति हेतु वार्ता प्रचलित है। वर्ष 2025-26 में 19 वृद्ध एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनसे आगामी समय में 7 लाख 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संचारण के लिये वर्ष 2025-26 में रुपये 17 हजार 863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 से 24 प्रतिशत अधिक है।

## निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, दिए निर्देश



ज्वालियर। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी वरिष्ठ अधिकारी निरंतर क्षेत्र में घूमकर स्वच्छता की मॉनिटरिंग करें तथा रोक साइड कहीं भी कचरा न दिखे यह स्वास्थ्य अमलते के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी भी सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री मुनीष सिंह सिकरवार, उपायुक्त श्री अमरसत्य गुप्ता, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश अहिवाल, कार्यशाला प्रभारी श्री पुणेन्द्र श्रीवास्तव, श्री बीबी चंसेलिया, मुख्य स्वच्छता अधिकारी डी अनुज शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री भीमा पामरानी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह सहित अन्य अमला मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने सर्वप्रथम छपरवाला पुल स्थित सुलभ शौचालय का निरीक्षण किया तथा आवश्यक जानकारी ली और निरंतर इसी प्रकार से सफाई रखने के निर्देश

दिए। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने नई सड़क पर शकरी कॉलोनी एवं अन्य आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और कचरा कलेक्शन कार्य को देखा, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर आमजन से चर्चा की और उनसे सफाई कार्य को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही महिला सफाई मित्र से चर्चा कर उनकी परेशानियों को जाना। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने नई सड़क स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर आमजन से चर्चा की। साथ ही कैलाश टॉकीज के पास पुराने कचराटिया का निरीक्षण किया तथा इसे आज की ही तरह निरंतर साफ रखने के निर्देश दिए। निगमायुक्त द्वारा सिटी सेंटर गोविंदपुरी सहित अन्य क्षेत्रों में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

## गंदगी फैलाने पर परम फूड गोविन्दपुरी पर लगाया 5 हजार का जुर्माना, अन्य क्षेत्रों में भी की गई जुर्माने की कार्रवाई

ज्वालियर। स्वच्छ ज्वालियर अभियान के तहत शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में गंदगी करने वाले एवं अमानक पॉलीथिन का उपयोग करने वाले एवं रेड स्पाट करने वाले लोगों को समझाईश के साथ ही नहीं मानने पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत आज परम फूड गोविन्दपुरी पर गंदगी फैलाने के लिए 5 हजार का एवं नई सड़क पर पालतू डॉग्स द्वारा सड़क पर गंदगी करने पर 250 रूप का जुर्माना लगाया गया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव एवं डॉ. अनुज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार उपायुक्त श्री अमर सत्य गुप्ता के निर्देशन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्वालियर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गंदगी करने वाले दुकानदारों एवं आमजन पर नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है। जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकारी श्री भीमा कुमार पामरानी के निर्देशन में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री रामचंद्र धोलपुरिया द्वारा जेलन 17 वार्ड 38 एवं वार्ड 39 में गंदगी करने पर



1800 रूप का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान डब्ल्यूएचओ श्री पूनम डगोर एवं राहुल धुरोल उपस्थित रहे। वहीं लखन क्षेत्र में घोड़ा द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाने पर फ्लाईंग स्पाट दण्डित द्वारा घोड़ा के मालिक पर 1000 रूप का जुर्माना किया गया। वहीं वार्ड 49 हरकोटाशीर में गंदगी करने पर 500 रूप का जुर्माना किया गया, कार्यवाही में डब्ल्यूएचओ श्री धर्मेन्द्र परमार, डब्ल्यूएचओ श्री लक्ष्मण चर्ध, डब्ल्यूएचओ श्री अरुण खरे उपस्थित रहे। इसके साथ ही जेलन 15 में सफाई व्यवस्था निरीक्षण के दौरान एक पेज ऑनर के द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर अपने डॉग्स के द्वारा गंदगी कराए जाने पर फ्लाईंग स्पाट दण्डित स्वास्थ्य अधिकारी श्री रामचंद्र धोलपुरिया द्वारा जेलन 17 वार्ड 38 वार्ड क्रमांक 53 में गंदगी फैलाने पर

500 रूप का जुर्माना किया गया एवं दो-दो डस्टबिन रखने की हिदायत दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी श्री किशोर चैहान के निर्देशन एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री गौरव सेन द्वारा वार्ड 29 स्थित गोविंदपुरी चैराहा पर परम रेस्टोरेंट के पीछे कचरा फैलाने पर परम फूड पर 5000 रूप का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी श्री अजय ठाकुर ज्वालियर विधानसभा के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 33 में अमानक पॉलीथिन उपयोग करने पर 1000 रूप का स्पाट पर जुर्माना किया गया। इस दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री सोनु वार्त्मीकि डब्ल्यूएचओ श्री मिथुन शर्मा, फ्लाईंग स्पाट टीम सदस्य श्री मनोज भारती, श्री वसंत करोसिया एवं श्री नरेश करोसिया उपस्थित रहे।

## थाना मोहना पुलिस ने एक बदमाश को पकड़कर उसके पास से 12 बोर एकनाली बंदूक व दो जिंदा राउण्ड किए जप्त

ज्वालियर। आगामी तौहार होली को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक ज्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापसे) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। इसी तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पब्लिक) श्री गजेन्द्र सिंह वर्धमान द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को सदिष्ट व्यक्तियों की चेकिंग कर अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एस्डीओपी घाटीगढ़ श्री शंकर दुबे के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोहना निरी0 रफीद खान के द्वारा थाना बल की टीम को क्षेत्र में सदिष्ट व्यक्तियों की चेकिंग कर अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु लगाया गया। दिनांक 12.03.2025 को थाना मोहना पुलिस को जरीये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मोहना क्षेत्र में डीआरडीओ के पीछे जंगल में एक व्यक्ति अवैध हथियार लिए वहाँ वारदात करने की नियत से बैठा है। उक्त सूचना पर से पुलिस टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर खाना किया गया। पुलिस टीम को डीआरडीओ के पीछे जंगल में मुखबिर के बताये हुलिया का एक सदिष्ट

व्यक्ति बंदूक लिये बैठा दिखा, जिसने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, परन्तु पुलिस टीम द्वारा उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पछुने पर उसने स्वयं को बरसाना मोहल्ला मोहना का रहने वाला बताया। पकड़े गये व्यक्ति के पास से 12 बोर एकनाली बंदूक व 2 जिन्दा कारतूस मिले। उक्त आरोपी का येन कृत्व 25,27 आम्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उसके पास से मिली 12 बोर एकनाली बंदूक व 2 जिन्दा कारतूस को विधिवत जप्त किया गया। पकड़े गये आरोपी के खिलाफ थाना मोहना में अप.क्र.0-27/25 धारा 25,27 आम्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना मोहना पुलिस द्वारा आरोपी से अवैध हथियार के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

बरामद मध्यरूका:- 12 बोर एकनाली बंदूक व 2 जिन्दा कारतूस। सराहनीय भूमिका:- थाना प्रभारी मोहना निरी0 रफीद खान, उनी0 सरनाम सिंह परमार, सज्जिन देवेन्द्र सिंह तोमर, सज्जिन राजेश तिवारी, प्र.आर0 सतनाम सिंह, आर0 रोहित शिवहरे, धानसिंह, रवि सूर्यवंशी, रामनिवास यादव, आर.चालक संजय रावत की सराहनीय भूमिका रही।

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड श्योपुर (म0प्र0) दूरमाष कमांक 07530-222185 Email id:- cephed\_sheopur@yahoo.com

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से म.प्र. लोक निर्माण विभाग में नवीन केन्द्रीयकृत पणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण के अपेक्षित 2.10 में प्रतिशत दर पर ई-निविदाये On-line आभारित की जाती है।  
कार्य का नाम- श्योपुर जिले के विकासखण्ड श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर के अन्तर्गत विभिन्न बसाहटों में 125/115 मि.मी व्यास के 90 मीटर गहरे साधारण नलकूप खनन/हेडरूप स्थापना प्रो.फार्म आदि निर्माण कार्य।  
ई-निविदा सूचना क्रमांक- 07530-222185 E-mail id:- cephed\_sheopur@yahoo.com  
दस्तावेजों की सूचना / प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना // 03-03-2025

क्र.	निविदा सूचना क्रमांक	टेंडर आई.डी.	विकास खण्ड	नलकूप की संख्या	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)	घरोहर राशि	निविदा प्रदान का मूल्य	समया बधि
1	23/2024-25 दि. 07.03.2025	2025_PHEID_408053	श्योपुर	18	12.98	25960	2000	02 माह
2	24/2024-25 दि. 07.03.2025	2025_PHEID_408055	कराहल	18	12.98	25960	2000	02 माह
3	25/2024-25 दि. 07.03.2025	2025_PHEID_408061	विजयपुर	18	12.98	25960	2000	02 माह

बिड सबमिशन प्रारम्भ दिनांक- 13.03.2025 समय 10.30 बजे से  
बिड सबमिशन अंतिम दिनांक- 22.03.2025 समय 17.30 बजे तक  
बिड खोलने का दिनांक- 24.03.2025 समय 13.00 बजे तक

नोट- यह निविदा का संक्षिप्त माग है। विस्तृत जानकारी अधोस्तराहकारकर्ता के कार्यालय अथवा वेब साइट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। नबिथ में स्थापित समस्त संशोधन उत्त वेब साइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे। संशोधनों का पृथक से प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
खण्ड श्योपुर (म0प्र0)  
G-24258/24







# कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की गेहूँ उपार्जन तथा पेयजल व्यवस्था की समीक्षा

**खरीदी केन्द्र में किसानों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें : कमिश्नर**  
**खराब हैण्डपंपों और नलजल योजनाओं के सुधार का अभियान चलाए : कमिश्नर**

रीवा, कांस। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों में गेहूँ उपार्जन की तैयारियों तथा पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि गेहूँ उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्रों का निर्धारण एक सप्ताह में कर दें। सभी खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए छाया, पानी, शौचालय, ढहने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। खरीदी से जुड़ी जानकारी के फ्लैक्स केन्द्र में लगवाएं। गेहूँ के सुरक्षित भण्डारण तथा असमय वर्षा से बचाव की व्यवस्था करें। खरीदी केन्द्र गोदाम स्तरीय बनाने को प्राथमिकता दें। खरीदी की निगरानी के लिए जिला और खण्ड स्तर के अधिकारी तैनात करें।

कमिश्नर ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी सभी जिलों में गेहूँ की अनुमानित मात्रा के अनुसार उपार्जन के लिए बारदानों को 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से भण्डारण करा दें। संभाग के सभी जिलों में फसल की स्थिति को देखते हुए उपार्जन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। गत वर्ष के उपार्जन के आधार पर



शासन को एक अप्रैल से उपार्जन शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव भेजें। सभी खरीदी केन्द्रों में तैलकाटे, छने, हम्माल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गोदामों में भण्डारित धान का मिलर्स द्वारा उठाव कराकर 25 मार्च तक गेहूँ उपार्जन के लिए गोदामों में व्यवस्था सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि संभागीय बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के लामान्वित हितग्राहियों के शत-प्रतिशत ई-केवाईसी के निर्देश दिए गए थे। सभी कलेक्टर 28 मार्च तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराएं। उपार्जन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित करें।

हैण्डपंपों के सुधार के लिए भी जिला और विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम बना दें। पीएचई विभाग की एकल नलजल योजनाओं का कार्य 31 मार्च तक पूरा कराकर उन्हें ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कराएं। सभी नगरीय निकायों तथा विकासखण्डों से पेयजल के संबंध में नियमित रूप से जानकारी लें।

जन सुनवाई तथा सीएम हेल्पलाइन में भी पेयजल व्यवस्था के संबंध में दर्ज शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराएं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में गेहूँ उपार्जन तथा पेयजल व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री पीएचई तथा उपार्जन से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। कमिश्नर कार्यालय संभागार से संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

## पीएम इंटरशिप योजना में युवाओं के पंजीयन के लिए लगाएं शिविर : कलेक्टर

रीवा, कांस। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 17 और 18 मार्च को पीएम इंटरशिप योजना में युवाओं के पंजीयन के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय सहित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के प्राचार्य अपने-अपने महाविद्यालयों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक पीएम इंटरशिप योजना में युवाओं के पंजीयन के लिए शिविर लगाएं। शिविर के लिए महाविद्यालय अपने

## जिले के सभी महाविद्यालयों में लगाए जाएंगे शिविर

स्तर से कंप्यूटर सिस्टम आदि की व्यवस्था करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। शिविर के बाद पंजीकृत आवेदन की सूची संभागीय आईटीआई के प्राचार्य की मेल आईडी पर भेजित करें। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा युवाओं को शीघ्र 500 कर्पिनियों में इंटरशिप एवं बेहतर मेंटॉरशिप दिलाने के उद्देश्य से पीएम इंटरशिप

योजना शुरू की गयी है। इस योजना का वर्तमान में दूसरा चरण जारी है। योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है। इस संबंध में प्राचार्य आईटीआई रीवा ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु 21 से 24 वर्ष के बीच है तथा सोधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित नहीं है और अन्य किसी ऑरिएंटेशन योजना का लाभ नहीं लिया है वे इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना के तहत हर माह 5 हजार रुपये इंटरशिप राशि एवं 6 हजार रुपये का ग्रांट भी दिया जायेगा।

## कलेक्टर ने ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश किए लागू

रीवा, कांस। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले भर में अत्यधिक तेज आवाज करने वाले ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत पूरे रीवा जिले में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने इस संबंध में बताया कि बोर्ड परीक्षाओं, पवित्र रमजान महीना तथा हेली पर्व को ध्यान रखकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। त्र्यहारां के दौरान कई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों तथा घरों के बाहर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही सड़कों पर जुलूस निकालते हैं जिससे आवागमन बाधित होता है। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती है। त्र्यहारां के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि

## तेज आवाज करने वाले ध्वनि यंत्रों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश शासन की गड्डाहलाइन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के 2023 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है। यह प्रतिबंध तेज आवाज करने वाले सभी ध्वनि विस्तार यंत्रों जैसे डीजे, साउंड बाक्स आदि पर लागू होगा। इनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से कोई उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तित्व तामीली संभव नहीं है। इसकाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से परित किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न संचार माध्यमों से प्रतिबंध की सूचना दी जा रही है। सभी एसडीएम कार्यालय, सभी थानों, नगरीय निकायों, जनपद पंचायत कार्यालयों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में भी प्रतिबंधात्मक आदेश नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया है।

## ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत योजनाओं में प्रगति के आधार पर ही सविदा अधिकारियों, कर्मचारियों की बढ़ेगी सेवा : कलेक्टर

### कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रीवा, कांस। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने बैठक में विभाग अन्तर्गत योजनाओं में काम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति के आधार पर ही सविदा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की आगामी सेवावृद्धि दी जायेगी। उन्होंने 31 मार्च तक नियत लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति के निर्देश बैठक में दिये।

कलेक्टर के मोहन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आवास योजना की समीक्षा के दौरान आवास प्लस में लंबित स्वीकृतियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि 67 प्रतिशत प्रगति को बढ़ाये तथा ब्लाक समन्वयक गंभीरता से कार्य करें उन्होंने रायपुर कसुलियान के ब्लाक समन्वयक का वेतन रोकने के निर्देश दिये। एसडीसी के वर्ष 2016-17 के आवासों को पूर्ण कराने तथा जो आवास पूर्ण नहीं हो सकते उनके संबंधित वे वसूली किये जाने के निर्देश बैठक में कलेक्टर द्वारा दिये गये। आवास प्लस 2.0 वर्ष में 94128 नये नाम जोड़े जाने पर कलेक्टर ने निर्देश किया कि जनपद सीईओ स्वयं सूची का परीक्षण करें तथा मौके पर भी जाकर वास्तविकता से प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सर्वे कार्य किया जाना है अतः कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें शामिल होने से छूटने न पाये।



स्वच्छता मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आगामी 15 दिनों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का संचालन अनुबन्ध कराकर कराने तथा निर्मित नाडेप का 15 अप्रैल तक शत प्रतिशत रायपुर कसुलियान के ब्लाक समन्वयक का वेतन रोकने के निर्देश दिये। एसडीसी के वर्ष 2016-17 के आवासों को पूर्ण कराने तथा जो आवास पूर्ण नहीं हो सकते उनके संबंधित वे वसूली किये जाने के निर्देश बैठक में कलेक्टर द्वारा दिये गये। आवास प्लस 2.0 वर्ष में 94128 नये नाम जोड़े जाने पर कलेक्टर ने निर्देश किया कि जनपद सीईओ स्वयं सूची का परीक्षण करें तथा मौके पर भी जाकर वास्तविकता से प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सर्वे कार्य किया जाना है अतः कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें शामिल होने से छूटने न पाये।

हों उसे पीएचई विभाग दूर करें। उन्होंने स्वसहयता समूहों से मध्यम भोजन का शत प्रतिशत संचालन कराने तथा समूहों को स्वच्छता के कार्य से सम्बद्ध करने के निर्देश दिये। मनरेगा से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों को पूरा करने तथा राज्य आयोजन मद से स्वीकृत आंगनवाड़ियों के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिये। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि 31 मार्च तक 808 आंगनवाड़ियों में विद्युत का कनेक्शन कराकर मीटर लगाकर कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने रीवा जनपद के सहायक यंत्री आर्द्रेयस का वेतन रोकने के भी निर्देश दिये तथा उपस्थित जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि ग्रामीण विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाये तथा मानीटरिंग करें। उन्होंने जिला पंचायत में पदस्थ अमले को भी योजनाओं की फील्ड में जाकर प्रगति की मानीटरिंग करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहाबा सिंह गुर्जर सहित जनपद के सीईओ तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## खेल/व्यापार

### समाचार

#### सेबी ने राइट्स इश्यू को पूरा करने की समयसीमा घटाकर 23 दिन की, 7 अप्रैल से लागू

मुंबई, ए.। कंपनियों को तेजी से पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने राइट्स इश्यू को पूरा करने की समयसीमा 126 दिनों से घटाकर 23 दिन कर दी है, जो 7 अप्रैल से प्रभावी होगा। एक संकूलन में, पूंजी बाजार नियामक ने राइट्स इश्यू में स्पेसिफिक निवेशकों को अलॉटमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान की है। सेबी ने कहा, नए फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, सेबी रेगुलेशन, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के संशोधित रेगुलेशन 85 के संदर्भ में, यह निर्दिष्ट किया जा रहा है कि राइट्स इश्यू को जारीकर्ता के निर्देशक मंडल द्वारा राइट्स इश्यू को मंजूरी देने की तारीख से 23 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें कहा गया है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 87 के अनुसार और रिवाइज्ड टाइमलाइन को देखते हुए यह निर्दिष्ट किया जा रहा है कि राइट्स इश्यू को सर्वक्रियान के लिए न्यूनतम सात दिन और अधिकतम तीस दिनों के लिए ओपन रखा जाएगा। बाजार नियामक के अनुसार, इस संकूलन के प्रावधान 7 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे तथा इस संकूलन के लागू होने की तिथि से इश्यूअर के निर्देशक मंडल द्वारा अफ़ूड राइट्स इश्यू पर लागू होंगे। इस बीच, 'यूजी अर्पाइटेड चेंबरपर्सन तुहिन कांत पांडे की लीडरशिप में आगामी पहली बोर्ड मीटिंग में सेबी कई प्रमुख विनियामक प्रस्तावों पर चर्चा करने वाला है। प्रस्तावित एजेंडे में डीमैट खातों के लिए यूपीआई जैसी सुविधा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, क्लॉलिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के दायरे का विस्तार करना और रिसर्च विश्लेषकों द्वारा फ्री कलेक्शन में बदलाव शामिल है। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेबी ने डीमैट खातों के लिए यूपीआई पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसा सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

#### सापाट खुला भारतीय शेयर बाजार, भारती एयरटेल रहा टॉप गेनर

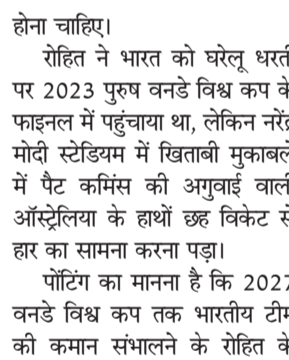
मुंबई, ए.। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सापाट रही। सुबह के कारोबार में ऑटो और पीएमयू बैंक सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सुबह करीब 9.28 बजे, सेंसेक्स 22.30 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 74,080.02 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 24.65 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 22,473.25 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी बैंक 231.40 अंक या 0.48 प्रतिशत बढ़कर 47,867.05 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 141.65 अंक या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 48,904.40 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 52.85 अंक या 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,128.75 पर था। बाजार पर नजर रखने वालों के अनुसार, सापाट शुरुआत के बाद, निफ्टी को 22,400 पर समर्थन मिल सकता है, उससे पहले इंडेक्स को 22,300 और 22,200 पर समर्थन मिल सकता है। ऊपरी स्तर पर, 22,600 तकाल प्रतिरोध हो सकता है और उसके बाद 22,700 और 22,800 स्तर तकाल प्रतिरोध हो सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के हार्दिक मतलिया ने कहा, वर्तमान में चल रही अस्थिरता को देखते हुए, ट्रेडर्स को सावधानी बरतने, सख्त स्टॉप-लॉस रणनीति लागू करने और ऑवरनाइट पोजिशन रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इस बीच, सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, जोमैटो, पावरग्रिड, सन फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप गेनर रहे। जबकि, इंडसस्ट्री बैंक, इण्डोसिस, एचसीएलएक और टीसीएस टॉप लुजर रहे। बाजार पर नजर रखने वालों के अनुसार, निवेशकों को शेयर बाजारों में निर-टर्म ट्रेड की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

## रोहित का वनडे से संन्यास नहीं लेने का मतलब उनका लक्ष्य 2027 विश्व कप खेलना है

**-ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग ने कहा**



नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग का मानना है कि रोहित शर्मा का वनडे से संन्यास नहीं लेने का मतलब है कि उनका लक्ष्य 2027 विश्व कप खेलना है। पॉटिंग ने भारत के पूर्व कप्तान के रूप में अपना दूसरा आईसीसी खिताब जीता, जब टीम ने दुबई में 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया। पिछले साल बाबाडोस में विश्व कप जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने टी20 प्रारूप से संन्यास लिया था, उसी तरह से रोहित के वनडे से संन्यास लेने की अपेक्षाएं चल रही थीं। लेकिन कप्तान, जिन्होंने 76 नंबर कप्तान प्लेयर ऑफ द फाइनाल का पुरस्कार जीता, ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन सभी बातों को खारिज कर दिया। जब आप अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंचते लगते हैं, तो हर कोई आपके संन्यास का इंतजार कर रहा होता है। पॉटिंग ने आईसीसी रिव्यू शो में कहा, और मुझे नहीं पता कि क्यों,



जब आप अभी भी उमरा ही अच्छे खेल सकते हैं जिना उन्हे (फाइनाल में) खेला है, तो मुझे लगता है कि वह सब उन सवालों को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे, नहीं, मैं अभी भी काफी अच्छे खेल रहा हूँ। मुझे इस टीम का नेतृत्व करना पसंद है। मुझे इस टीम का नेतृत्व करना पसंद है। और मुझे लगता है, तथ्य यह है कि उन्होंने ऐसा कहा, मेरे लिए, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में अगले (50 ओवर) विश्व कप (2027 में) में खेलने का लक्ष्य

## मैं आईपीएल में खिलाड़ियों को रिलीज करने के नियम को बदल दूंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2025 सीजन से पहले, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजु सैमसन ने कहा कि उनके करीबी दोस्त, विकेटकीपर-ओपनर जोस बटलर को जाने देना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था और अगर उनके पास आईपीएल में कोई नियम बदलने की शक्ति होती, तो वह खिलाड़ियों को कभी रिलीज न करने देते। आरआर ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में पैट कमिंस की मुकामवाली आईपीएल के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पॉटिंग का मानना है कि 2027 वनडे विश्व कप तक भारतीय टीम की कप्तान संभालने के रोहित के फैसले के पीछे आशुषा का नाम होने की भावना हो सकती है, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शायद यह तथ्य कि वे पिछला मैच हार गए थे और वह कप्तान थे, शायद यही बात उनके दिमाग में चल रही है। टी20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे विश्व कप जीतने की कोशिश में सब एक और मौका है। मेरा मतलब है, जब आप उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तरह खेलते हुए देखेंगे, तो आप यह नहीं कहेंगे कि उनका समय अभी खत्म हो गया है।



सकारात्मक पक्ष यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वॉश से बने संपर्क और रिश्ते खो देते हैं। यह मेरे लिए, पूरी फ्रेंचवाइजी, मालिकों, कोचों और आरआर से जुड़े सभी लोगों के लिए कठिन रहा है। जोस हमारे लिए परिवार की तरह थे। साथ ही, सैमसन ने जुंरल, पराग और डेटामार जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को बनाए रखने के प्रयास पर भी बात की। बेशक, यह एक बड़ी भूमिका निभाता है। पहले से ही टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों का होना एक बेहतरीन संबंध बनाता है। इससे मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि हम मैदान पर और बाहर दोनों जगह एक-दूसरे को अच्छे तरह से जानते हैं और इससे टीम के बेहतर समन्वय में मदद मिलती है। पिछले साल की मेगा नीलामी में, आरआर ने 13 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को साइन करके तहरका मचा दिया था, जो अब आईपीएल डील हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।

## बल्लेबाजी में उतार-चढ़ाव के बावजूद सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गए केएल राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑसिलेटरी मोशन की विशेषता एक निश्चित बिंदु के बारे में किसी वस्तु की बार-बार आगे-पीछे की गति है, जैसा कि चूड़ी के पेंडुलम द्वारा उदाहरण दिया गया है। भारतीय टीम में सबसे अधिक ऑसिलेटरी खिलाड़ी को खोजने की प्रतियोगिता में, केएल राहुल सर्वसम्मति से चुने जायेंगे। राहुल के शानदार कवर ड्राइव और उनकी कलाई से सहज फ्लिक, जब वे अपने सर्वश्रेष्ठ पर होते हैं, तो बस गति में कविता होती है। लेकिन राहुल होना आसान नहीं है - उनकी बल्लेबाजी की स्थिति में उतार-चढ़ाव चुनौतीपूर्ण रहे हैं, एक पेंडुलम की आगे-पीछे की गति के समान। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दौरान भारत के लिए मैच फिनिशर करने में राहुल की सफलता इसका उदाहरण



है। राहुल को एकदिवसीय मैचों में नई चुनौती का सामना करना पड़ा, जब उन्हें छठे स्थान पर भेजा गया, जो कि अक्षर पटेल के अपने सामान्य नंबर पांच पर आने के बाद फिनिशर की स्थिति थी। इसके अलावा, इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में, हमेशा इस बात पर

सवाल उठते रहे कि राहुल को मध्य पंत से आगे क्यों तरजोह दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए उस भूमिका में राहुल की सफलता उनके शांत, विनम्र और सतिय अनुकूलनशीलता से चिह्नित थी - ऐसे गुण जो उनके लिए दूसरी प्रकृति बन गए हैं। हालांकि उनके 136 ट्वेंटीम ट्वेंटी रन महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन वे भारत के निचले मध्य क्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की पूरी कल्पना नहीं बताते हैं। केएल राहुल के बचपन के कोच सैमुअल जयराज ने कहा, जब भी उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजा जाता था, तो वे शिकायत नहीं करते थे। वे मुझे पूछते थे कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ और मुझे उस तरह से बचाने के लिए सलाह चाहिए। देखिए, जब भी वे छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने जाते हैं, तो मुश्किल से कुछ गंदे होती

हैं। उन्होंने हमेशा बल्लेबाजी की है, चाहे वे कहीं भी खेले हों। इसलिए मानसिकता में बदलाव और परिस्थिति के अनुसार खुद को खलना, यह सब नया है। उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन यह भूमिका अलग थी और उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। योजना और तैयारी अच्छी थी, इसलिए वह अच्छे खेल सके। वह अपनी भूमिका समझते थे और अगर आपने फाइनल देखा हो, तो जब बाएं हाथ के स्पिनर गेंदाबाजी कर रहे थे, तो वह आसानी से पीछे, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच सिलान लेते थे। उनकी योजना अच्छी थी और उन्होंने इसे इस तरह से प्लान किया कि हां, मुझे यह करना है। मुझे लाइन पर करनी है और देश के लिए मैच जीतना है।











# विधायक गुर्जर ने पत्रकारों की सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार की समस्याओं को विधानसभा में उठाया

**मुरैना विधानसभा के विकास, पत्रकारों की सुरक्षा, बानमौर आवास कॉलोनी में सड़क, पानी, बिजली की समस्या, क्षेत्रीय नौजवानों के रोजगार एवं सभागीय कार्यालयों की स्थापना, शिक्षा आदि समस्याओं को लेकर भोपाल विधानसभा में गजरे: विधायक मुरैना दिनेश गुर्जर**

मुरैना, कांस। विगत दिनों भोपाल में चल रही विधानसभा में मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने याचिका के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, तारकित और अतारकित प्रश्नों के माध्यम से मुरैना विधानसभा क्षेत्र के विकास, रोजगार, पत्रकारों की सुरक्षा और जनहित कार्यों के लिए अपनी बात रख मांग की और कहा कि वर्तमान में पत्रकारों पर बिना जांच के सड़क कर दी जाती है, सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए आवास, वेतन, स्वास्थ्य एवं पेंशन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में कोई दिशा निर्देश है क्या जानकारी ली एवं पत्रकार सुरक्षा कानून कब तक लागू किया जाएगा, कानून लागू नहीं किए जाने के पीछे क्या कारण है शासन द्वारा पत्रकारों को उनके काम करने की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की और चंबल संभाग बनाने के बाद किस-किस विभाग के सभागीय कार्यालय मुरैना में खोले जाने थे एवं मुरैना में वर्तमान में कौन-कौन से संचालित हैं उनकी



जानकारी ली एवं चंबल संभाग का सभागीय कार्यालय स्कूल शिक्षा, आई.टी.आई., स्वास्थ्य विभाग, कोष लेखा आदि जो आज दिनांक तक नहीं खोले गए हैं उनको खोलने के आदेश जारी करने की मांग की और विधानसभा क्षेत्र मुरैना के अंतर्गत ग्राम पंचायत देरावली के अंतर्गत जरेरुआ औद्योगिक क्षेत्र मुख्य मार्ग से निहाल सिंह का पुरा से पंचम सिंह सरपंच के पुरा से कल्लर का पुरा, कंसना पुरा, वीरेंद्र सिंह के पुरा तक

आने-जाने हेतु सड़क न होने से जनता बहुत परेशान हो रही है बरसात के समय में लोगों का आना-जाना बंद हो जाता है जिस कारण ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लगभग 2 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य कराने की मांग की एवं ग्राम पंचायत खिरवली के अंतर्गत छर्वा का पुरा, ग्राम पंचायत बमरोली के ग्राम विसंठ, ग्राम पंचायत बैड़ा के अंतर्गत घुरैया साह का पुरा एवं अन्य

ग्राम पंचायतों में जो एडि्ट शालाएं खुली थीं उनमें शिक्षक रिटायर्ड होने से एडि्ट शालाएं बंद हो गई हैं जिस कारण ग्रामवासियों के बच्चे अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अन्य ग्रामों में जाना पड़ता है जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए नवीन प्राथमिक शालाएं खोली जावे और उनमें शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की और ग्राम पंचायत पहड़ी हर्षना का पुरा के पास बने डेम की पार बाढ़ आने से टूट गई, जिससे किसानों की फसलों में पानी भर रहा है नुकसान हो रहा है डेम का पानी भी कम हो रहा है एवं पिलुआ डेम खंग का पुरा नहर की दीवार को ऊंचा करने की भी मांग की।

## स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित आईएसबीटी के संचालन और रखरखाव संबंधित निविदा प्रक्रिया को जल्द पूरा करें - कलेक्टर

**अधिकारियों की बैठक लेकर की आईएसबीटी के O&M की समीक्षा, नगर निगम आयुक्त भी बैठक में रहे मौजूद, प्राप्त सुझावों के आधार पर संबंधित सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का संयुक्त दल मिलकर करेगा सर्वे**

ज्वालियर। ज्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा नवनिर्मित इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के संचालन और रखरखाव संबंधी निविदा प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ताकि शहरवासियों को इस नवनिर्मित आईएसबीटी का लाभ मिल सके साथ ही शहर के विकास में नया आयाम जुड़ सके। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित आईएसबीटी के संचालन और रखरखाव की निविदा योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कार्य हेतु बनाई जा रही निविदा में वह सभी जरूरी प्रावधानों को शामिल किया जाए जो भविष्य में आईएसबीटी के सुचारु संचालन और बेहतर रखरखाव के लिए जरूरी हो। बैठक में स्मार्ट सिटी के सीओ एवं नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय भी मौजूद थे। बुधवार को मोतीमहल स्थित स्मार्ट सिटी के सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आईएसबीटी से बसों के संचालन व इसके रखरखाव की योजना की विस्तार से समीक्षा की।



साथ ही इस हेतु तैयार प्रारंभिक निविदा ड्राफ्ट के बिन्दुओं पर भी चर्चा की। बैठक में श्रीमती चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईएसबीटी के लैंड यूज संबंधित जरूरी प्रक्रिया को संबंधित टोपेंडेंसीपी विभाग के साथ समन्वय कर पूरा करें व स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में भी रखें। वहीं उन्होंने आईएसबीटी पर जरूरी सेवाओं जैसे हैल्प डेस्क, चिकित्सीय सहायता, पुलिस सहायता केंद्र सहित अन्य सेवाओं का प्रावधान रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीमती चौहान ने आईएसबीटी पर जरूरी सरकारी उपक्रमों के लिए भी अलग से जगह चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आईएसबीटी में महिला कमियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में मौजूद नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने आईएसबीटी के संचालन और रखरखाव को लेकर तैयार किए जाने वाली निविदा में हर तकनीकी पहलु को अच्छे से देखकर तैयार करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के अंत में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गुरुवार 13 मार्च को आईएसबीटी से सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से बस स्टॉप का सर्वे करने की बात भी कही।

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**राजा दिनेश सिंह**  
थाना इंचार्ज, थाना-बार  
जनपद - ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**मोहम्मद मुश्ताक**  
पुलिस अधीक्षक, ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**श्रीमती रुपादेवी यादव**  
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत लखनपुर  
जनपद - ललितपुर  
प्रधान प्रतिनिधि-सुखसिंह यादव

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**राहुल कुमार**  
चौकी इंचार्ज, चौकी मसौराकाला,  
जनपद - ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**पं. निखिल तिवारी**  
जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी  
जनपद - ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**गंधर्वसिंह लोधी (बाबूजी)  
एवं सोरभ लोधी**  
वरिष्ठ कार्यकर्ता, भा.ज.पा.  
जनपद - ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**पं. कृष्णा शर्मा (गोलू)**  
नगर मंत्री भा.ज.पा.यु.मो.,  
ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**कुलदीप राणा**  
चौकी इंचार्ज, चौकी बांसी,  
जनपद - ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**अभय नारायण राय**  
क्षेत्राधिकारी, सदर, ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**अक्षय त्रिपाठी**  
जिलाधिकारी, ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**डॉ. पासनाय यादव/डॉ. सोरभ यादव**  
प्रबन्धक,  
पहलवान गुरुद्वीप बुध ऑफ कॉलेज पनारी,  
जनपद - ललितपुर

समस्त जनपदवासियों, इष्ट मित्रों को  
रंगों के पावन पर्व

# हल्ली

की  
हार्दिक शुभकामनाएं

**रणवीर सिंह**  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,  
ललितपुर